RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

DPR No. N-193
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 13 MARCH TO 19 MARCH 2024 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 09 ■ अंक 25 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

क्रैश हुआ शेयर बाजार, रु.13 लाख करोड़ डूबे Page 3

पेटीएम पर 15 मार्च के बाद नहीं कर पाएंगे फास्टैग रिचार्ज Page 4

10 लाख जॉब्स, 100 अरब डॉलर का निवेश और सस्ते होंगे यूरोपीय प्रोडक्ट्स Page 5

editoria!

बढ़ती रक्षा क्षमता

मिशन दिव्यास्त्र का सफल परीक्षण भारत की सामरिक क्षमता के विस्तार में एक महत्वपूर्ण कदम है. देश में ही विकसित अग्नि 5 मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल री-एंट्री व्हिकल तकनीक से लैस है. इस तकनीक से एक ही मिसाइल में अनेक बम जोड़े जा सकते हैं, जिन्हें अलग-अलग जगहों पर या एक ही जगह पर अलग-अलग समय दागा जा सकता है. मिसाइल रोधी हमले से बचाव के लिए नकली बम भी इस मिसाइल के साथ भेजे जा सकते हैं, जो शत्रु को चकमा दे सकते हैं. इस मिसाइल में छह हजार किलोमीटर तक मार करने की क्षमता है तथा इससे परमाणु बम भी दागे जा सकते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभालने के साथ ही रक्षा क्षमता को अत्याधुनिक तकनीक एवं हथियारों से युक्त करने का काम प्रारंभ कर दिया था. साथ ही, सरकार रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से देश में ही निर्माण और उत्पादन को बढ़ावा दे रही है. अग्नि-5 की पहली उड़ान ऐसे प्रयास की सफलता का महत्वपूर्ण उदाहरण है. उल्लेखनीय है कि एक साथ कई हथियार ढोने की मिसाइल तकनीक साठ के दशक में ही खोज ली गयी थी और सभी ताकतवर देशों के पास ऐसी मिसाइलें हैं. अमेरिका में सत्तर के दशक के प्रारंभ में ऐसी मिसाइल का परीक्षण हुआ था, जबकि सोवियत संघ ने कुछ साल बाद ऐसी मिसाइल बनाने में कामयाबी पायी. भारत ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर इस तकनीक के इस्तेमाल की घोषणा की है. यह घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के पोस्ट द्वारा की है. यह भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और स्वाभिमान को भी इंगित करता है. अब भारत ऐसी क्षमता वाले देशों- अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन की कतार में आ गया है. हमारे दो आक्रामक पड़ोसियों- चीन और पाकिस्तान- लगातार अपनी रक्षा शक्ति को बढ़ाने में लगे हुए हैं. ऐसे में हमें भी अपनी सामरिक तैयारी को बेहतर करते जाना है. कई बम ढोने की मिसाइल तकनीक चीन के पास पहले से ही है और पाकिस्तान भी ऐसी मिसाइलों को विकसित कर रहा है. पिछले वर्ष अक्टूबर में पाकिस्तान ने मध्य दूरी के एक बैलेस्टिक मिसाइल का दूसरा परीक्षण किया था, जिसे कई हथियारों को ढोने के लिहाज से डिजाइन किया गया है. अग्नि-5 का पहला परीक्षण 2012 में किया गया था. उसी समय से इस उत्कृष्ट तकनीक को उससे जोड़ने के प्रयास हो रहे थे. इस मिसाइल में देश में ही विकसित तंत्र, सेंसर आदि लगे हुए हैं. हालिया परीक्षण हमारी सामरिक शक्ति बढ़ाने की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्र में हमारी प्रगति का भी उदाहरण है.

सीपीआई डेटा, ओपेक की रिपोर्ट से तेल की कीमतें बढ़ीं

एजेंसी

मंगलवार को एशियाई व्यापार में तेल की कीमतें थोड़ी बढ़ गईं, प्रमुख अमेरिकी मुद्रास्फीति डेटा से पहले बाजार काफी हद तक सतर्क रहे, जो कि ब्याज दरों में कारक होने की संभावना है, जबकि ओपेक की आगामी मासिक रिपोर्ट पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था। मई में समाप्त होने वाला ब्रेंट ऑयल वायदा 0.3ङ्ग बढ़कर 82.43 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड वायदा 22:01 ईटी (02:01 जीएमटी) तक 0.3ङ्ग बढ़कर 77.77 डॉलर प्रति बैरल हो गया। .

कच्चे तेल के बाजार मिश्रित मांग, आपूर्ति संकेतों से जूझ रहे हैं

मांग और आपूर्ति पर परस्पर विरोधी संकेतों के बीच, हाल के सत्रों में कच्चे तेल की कीमतें काफी हद तक सीमित रहीं। ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई वायदा पिछले तीन हफ्तों से 85 डॉलर प्रति बैरल से 75 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में कारोबार कर रहे हैं। चीन तेल बाज़ारों के लिए विवाद का एक प्रमुख मुद्दा था, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातक की मांग गिरती दिख रही थी और तत्काल सुधार की बहुत कम उम्मीदें थीं। बीजिंग ने 2024 के लिए मध्यम विकास लक्ष्य निर्धारित किया, और अधिक प्रोत्साहन उपायों पर भी अल्प संकेत दिए। चीन को लेकर चिंताएं कुछ हद तक अमेरिका की बढ़ती उम्मीदों से कम हो गईं। कच्चे तेल की मांग में कमी आई है, क्योंकि देश में कई रिफाइनर्स ने एक विस्तारित ब्रेक के बाद उत्पादन बढ़ाना शुरू कर दिया है। लेकिन देश का कच्चे तेल का उत्पादन प्रति दिन 13 मिलियन बैरल से अधिक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर रहा।

बाजार अब मांग पर अधिक संकेतों के लिए पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन से मासिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, खासकर कार्टेल ने कहा था कि वह जून के अंत तक उत्पादन में कटौती की अपनी वर्तमान गति को बनाए रखेगा। आपूर्ति के मोर्चे पर, इज़राइल-हमास युद्ध में थोड़ी कमी के संकेत, विशेष रूप से युद्धविराम वार्ता विफल होने के संकेत, मध्य पूर्व में निरंतर आपूर्ति जोखिमों की ओर इशारा करते हैं।

लाल सागर में यमनी हौथी समूह के साथ संघर्ष ने भी क्षेत्र में शिपिंग गतिविधि में लगातार व्यवधान उत्पन्न किया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक मासिक रिपोर्ट भी इस सप्ताह के अंत में आने वाली है। यूएस सीपीआई ब्याज दर संकेतों का इंतजार कर रहा है तेल बाजार भी प्रमुख अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक डेटा से पहले काफी हद तक सतर्क थे, जो मंगलवार को बाद में आना है। उम्मीद है कि रीडिंग से पता चलेगा कि मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है और फरवरी में फेडरल रिजर्व के 2ङ्ग वार्षिक लक्ष्य से काफी ऊपर है। मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी के किसी भी संकेत से फेड की ओर से अधिक कठोर दृष्टिकोण अपनाने की संभावना है, जिससे अमेरिकी ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहेंगी। फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने पिछले सप्ताह चेतावनी दी थी कि 2024 में कोई भी संभावित ब्याज दर में कटौती काफी हद तक मुद्रास्फीति की राह पर निर्भर करेगी।

कच्चे तेल की कीमत में कमी का असर अरामको का मुनाफा 25 प्रतिशत गिरा

एजेंसी

सऊदी अरब की सरकारी तेल उत्पादक कंपनी को अरामको ने 2023 में 121.3 अरब डॉलर का मुनाफा दर्ज किया है। यह 2022 के मुनाफे के मुकाबले 25 प्रतिशत कम है। पिछले साल कंपनी को 161 अरब डॉलर का मुनाफा हुआ था। कंपनी की ओर से मुनाफे में कमी की वजह तेल की कीमतों के साथ उत्पादन में गिरावट होना है।

कंपनी ने बढ़ाया डिविडेंड

मुनाफे में कमी के बावजूद कंपनी की ओर से चौथी तिमाही के डिविडेंड को 4 प्रतिशत बढ़ाकर 20.3 अरब डॉलर और परफॉरमेंस लिंक्ड डिविडेंड को 9 प्रतिशत बढ़ाकर 10.8 अरब डॉलर कर दिया गया है। इस तरह कुल 31 अरब डॉलर का डिविडेंड सऊदी सरकार और अरामको के शेयरधारकों को लिया जाएगा। कंपनी का 82 प्रतिशत हिस्सा सऊदी सरकार और 16 प्रतिशत हिस्सा देश के वेल्थ फंड की ओर से नियंत्रित किया जाता है।

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में बताया गया कि अरामको ने रियाद के तदावुल शेयर बाजार को यह जानकारी देते हुए कहा कि मुनाफे में गिरावट की वजह से कच्चे तेल के दाम में कमी और बिक्री में कमी आना है। इसके अलावा रिफाइनिंग मार्जिन में भी कमी आई है। कंपनी सोमवार को अपनी वित्तीय नतीजों पर चर्चा के लिए कॉन्फ्रेंस कॉल करेगी। 2023 में कंपनी का राजस्व घटकर 440 अरब डॉलर रह गया। 2022 में यह 535 अरब डॉलर था।

कंपनी ने किया रिकॉर्ड उत्पादन

अरामको केसीईओ अमीन एच नासिर ने बयान में कहा कि आर्थिक मोर्चे पर अड़चनों के बावजूद नकदी प्रवाह और मुनाफा ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। 2023 में कंपनी ने रिकॉर्ड 102.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का उत्पादन किया है और मांग को देखते हुए इसमें आगे भी वृद्धि होने के अनुमान है।

सऊदी अरामको

सऊदी अरामको, सऊदी अरब की सरकार तेल कंपनी है, जो कि पैट्रोलियम के साथ नेचुरल गैस का उत्पादन करती है। आय के मामले में ये 2022 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी।

सरकारी कैंटीन का सामान होगा और सस्ता

मोदी सरकार ने 20 लाख कर्मचारियों को किया खुश

एजेंसी

केंद्र सरकार ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (CAPF) के जवानों को तोहफा दिया है। सीएपीएफ (CAPF) के जवानों को कैंटीन में मिलने वाले प्रोडक्ट पर 50 प्रतिशत की जीएसटी छूट मिलेगी। पूर्व अर्धसैनिक बलों के वेलफेयर से जुड़े संगठन ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। यह छूट केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार (KPKB) के लिए नोटिफाई की गई है। केपीकेबी (KPKB) की तरफ से देश के अलग-अलग राज्यों में मौजूदा 1700 से ज्यादा कैंटीन का संचालन किया जाता है।

इस तरह के कर्मचारियों को मिलता है फायदा

केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) में सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी शामिल हैं। इन कैंटीन की सुविधा का गृह मंत्रालय से जुड़ी कुछ अन्य संस्था जैसे बीआरपीएफ और एनसीआरबी के कर्मचारियों को भी दिया जाता है। इन सुरक्षाबलों के पास देश-विदेश में अलग-अलग प्रकार की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है।

जीएसटी का 50% हिस्सा सरकार देगी

कंफेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज मार्टियर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इसे 20 लाख से ज्यादा देश सेवा कर रहे और रिटायर हो चुके अर्धसैनिक बल के कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए होली का तोहफा बताया। रणबीर सिंह ने बताया कि कैंटीन से सामान खरीदने पर लगने वाले जीएसटी का 50% हिस्सा सरकार देगी।

कब से किया जाएगा लागू

जीएसटी में दी जाने वाली छूट को अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से दी गई राहत में खर्च होने वाले पैसे को सुरक्षा बलों के लिए आवंटित किये गए बजट से ही लिया जाएगा। आपको बता दें केंद्रीय पुलिस कैंटीन हर साल करीब 10 लाख कर्मियों के 50 लाख परिजनों और रिटायर्ड कर्मियों व उनके परिवारों वालों को घरेलू जरूरत के सामान की बिक्री करती हैं। इन सामानों में किराना, कपड़े और गाड़ियों आदि की बिक्री शामिल होती है। इस तरह के सामान की बिक्री कर हर साल करीब 2800 करोड़ रुपये का कारोबार किया जाता है।

देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ा उछाल

RBI के खजाने में अब अरबों डॉलर का Forex Reserves

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ा उछाल आया है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जानकारी दी गई जानकारी के मुताबिक, देश का विदेशी मुद्रा भंडार एक मार्च को समाप्त सप्ताह में 6.55 अरब डॉलर बढ़कर 625.63 अरब डॉलर हो गया। इससे एक सप्ताह पहले कुल विदेशी मुद्रा भंडार 2.97 अरब डॉलर बढ़कर 619.07 अरब डॉलर रहा था। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2021 में, देश का विदेशी मुद्राभंडार 645 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। पिछले साल से वैश्विक गतिविधियों के कारण उत्पन्न दबाव के बीच केंद्रीय बैंक ने रुपये की गिरावट को रोकने के लिए पूंजी भंडार का उपयोग किया जिससे मुद्रा भंडार प्रभावित हुआ।

विदेशी मुद्रा भंडार में ये घटक शामिल

रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, एक मार्च को समाप्त सप्ताह में मुद्राभंडार का अहम हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां 6.04 अरब डॉलर बढ़कर 554.23 अरब डॉलर हो गयी। डॉलर के संदर्भ में उल्लेखित विदेशी मुद्रा आस्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं की घट-बढ़ का प्रभाव शामिल होता है। रिजर्व बैंक ने कहा कि सप्ताह के दौरान स्वर्ण आरक्षित भंडार का मूल्य 56.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 48.42 अरब डॉलर हो गया। रिजर्व बैंक ने कहा कि विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 1.7 करोड़ डॉलर घटकर 18.18 अरब डॉलर रहा। रिजर्व बैंक के मुताबिक समीक्षाधीन सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के पास भारत की आरक्षित जमा भी 4.1 करोड़ डॉलर घटकर 4.79 अरब डॉलर रहा।

क्या है Golden Hour स्कीम जिसका जल्द ऐलान कर सकती है सरकार? मिलेगा फ्री कैशलेस ट्रीटमेंट

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सरकार सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों की मदद के लिए जल्द ही एक नई स्कीम का ऐलान कर सकती है। इसका नाम 'गोल्डन ऑवर' स्कीम है। नई स्कीम के तहत दुर्घटना के पहले 60 मिनट के भीतर 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज या 7-10 दिन तक का हॉस्पिटलाइजेशन (जो भी कम हो) मुहैया कराया जाएगा। यह पहल मोटर वाहन अधिनियम 2019 (MAV2019) का हिस्सा है। इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। 'गोल्डन ऑवर' शब्द सड़क दुर्घटना के बाद के उस महत्वपूर्ण 60 मिनट के समय को बताता है जिस दौरान तुरंत चिकित्सा ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी होता है।

बीमा कंपनियां वहन करेंगी खर्च

खबरों के अनुसार, इस परियोजना को फंड करने के लिए बीमा कंपनियां अपने प्रीमियम का

0.5 फीसदी कॉन्ट्रिब्यूशन देंगी। यह लगभग 100 करोड़ रुपये होगा। सरकार हरियाणा और चंडीगढ़ में एक पायलट प्रोग्राम शुरू करके इस योजना की प्रभावशीलता का परीक्षण करने की योजना बना रही है। इस पहल का मकसद 'गोल्डन ऑवर' ट्रीटमेंट के जरिये सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50 फीसदी तक कम करना है। 2022 में भारत में 1.68 लाख सड़क दुर्घटनाओं में मौतें हुईं।

आयुष्मान भारत अस्पतालों के जरिये मिलेगी सुविधा

सरकार ने इंजीनियरिंग के जरिये वाहन सुरक्षा बढ़ाने के लिए पहले से ही कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें ABS और ओवर-स्पीडिंग अलर्ट सिस्टम को अनिवार्य करना, सीट बेल्ट रिमाइंडर शुरू करना और नया भारत NCAP क्रैश सेफ्टी रेटिंग टेस्ट लागू करना शामिल है। 'गोल्डन आवर' स्कीम के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को देशभर के आयुष्मान भारत-एमपैनल्ड अस्पतालों में चिकित्सा देखभाल प्राप्त होगी। ट्रीटमेंट की ऊपरी सीमा 1.5 लाख रुपये होगी। इसमें अस्पताल में भर्ती होने के 10 दिन तक का समय शामिल होगा। इलाज का खर्च बीमा कंपनियां वहन करेंगी। सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से किए गए आकलन के अनुसार, सड़क दुर्घटना के लगभग 97 फीसदी मामलों में औसत चिकित्सा खर्च लगभग 60 हजार रुपये है। केवल कुछ ही पीड़ितों को लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने और गहन देखभाल की जरूरत होती है।

भारत में टेस्ला को बड़ा झटका! नहीं मिलेगी कोई खास छूट

पीयूष गोयल ने कही ये बड़ी बात

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत अपनी नीतियों को अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी टेस्ला के हिसाब से नहीं बनाएगा। देश के कानून और शुल्क संबंधी नियम सभी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) विनिर्माताओं को आकर्षित करने के लिए तैयार किए जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह बात कही है। एलन मस्क की टेस्ला भारत में आने से पहले एक शुरुआती शुल्क रियायत मांग रही है। इससे उसे 40,000 अमेरिकी डॉलर से कम कीमत वाली कारों के लिए 70% सीमा शुल्क और अधिक मूल्य की कारों के लिए 100% सीमा शुल्क की 'भरपाई' करने में मदद मिलेगी। गोयल ने पीटीआई-भाषा के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि सरकार एक मजबूत ईवी इकोसिस्टम की जरूरत को समझती है, क्योंकि बैटरी से चलने वाले वाहनों के अधिक उपयोग से कार्बन उत्सर्जन के साथ-साथ कच्चे तेल के आयात बिल में भी कटौती होगी। उन्होंने साथ ही जोड़ा कि इसके लिए सरकार ऐसी नीतियां नहीं बनाएगी, जो किसी एक कंपनी के लिए फायदेमंद हों, बल्कि ऐसी नीतियां तैयार की जाएंगी, जो दुनिया के सभी इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं को भारत में आने के लिए प्रोत्साहित करें।

निवेशकों से चल रही बातचीत

उन्होंने कहा कि इस संबंध में कई पहल पर काम जारी है, और अंतर-मंत्रालयी परामर्श और हितधारकों के साथ बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा कि यूरोप, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और दुनियाभर के संभावित निवेशकों के साथ भी संवाद चल रहा है। भारत में मोटर वाहनों पर उच्च शुल्क लागू है, जिसका मकसद घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। विदेशी कार विनिर्माताओं के लिए यह एक बड़ा मुद्दा है।

मांग रखने के लिए स्वतंत्र

उन्होंने कहा, "सरकार किसी एक कंपनी या उसके हितों के लिए नीति नहीं बनाती है। सभी अपनी मांग रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार उनकी मांग के आधार पर फैसला करेगी।" गोयल इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या सरकार भारत में विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए टेस्ला को कोई रियायत देने पर विचार कर रही है।

सरकार ने आधार कार्ड पर दी बड़ी राहत

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने आधार कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार को फ्री में अपडेट कराने के डेटलाइन एक बार फिर बढ़ा दी है। फ्री में आधार को अपडेट कराने की अंतिम तारीख 14 मार्च 2024 थी। यह खत्म होने वाली थी। अब इसे बढ़ा दिया गया है। अब यूजर्स अगले साल यानी 14 जून 2024 तक फ्री में अपने आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं। UIDAI की ओर से अंतिम तारीख को बढ़ाए जाने से लोगों को काफी राहत मिली है। अब लोग आराम से अपने आधार कार्ड को अपडेट करा सकेंगे। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से भी ज्यादा पुराना हो गया है तो आप आसानी से ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोसेस के जरिए उसे अपडेट कर सकते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार को फ्री में अपडेट कराने के डेटलाइन बढ़ाने के बाद अब लोगों को 50 रुपये की फीस नहीं भरनी पड़ेगी। भारतीय नागरिकों के पास फ्री में डेमोग्राफिक जानकारी, अड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल करेक्ट करवाने का मौका है। अब इसके लिए उन्हें अलग से कोई शुल्क नहीं देना होगा। आधार में सभी डेमोग्राफिक जानकारी अपडेट करना बिल्कुल फ्री है। वहीं आप इसे घर बैठे ऑनलाइन भी अपडेट करा सकते हैं। हालांकि फोटोग्राफ, iris या अन्य बायोमेट्रिक डिटेल अपडेट करवाना चाहता है तो उसे आधार एनरोलमेंट सेंटर जाना होगा।

क्रैश हुआ शेयर बाजार, रु.13 लाख करोड़ डूबे

सेबी चेयरपर्सन का सख्त बयान

सेबी चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच ने कहा- हमारे पास इस बारे में पता लगाने की तकनीक है। हम कुछ पैटर्न देख रहे हैं। मैं कहूंगी कि यह अभी शुरुआती चरण में है और बात बहुत आगे नहीं बढ़ी है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को शेयर बाजार में भूचाल आ गया। दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स 1500 अंक से ज्यादा टूटकर 72,515 अंक तक आ गया। वहीं, ट्रेडिंग के दौरान शेयर की कीमत 74052 रुपये के हाई तक पहुंच गई। निफ्टी की बात करें तो 400 अंक से ज्यादा लुढ़ककर 21905 अंक के निचले स्तर तक पहुंच गया। इस बड़ी गिरावट की वजह से निवेशकों को करीब 13 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 906 अंक गिरकर 72,762 पर और निफ्टी 338 अंक गिरकर 21,998 पर आ गया।

स्मॉलकैप इंडेक्स का हाहाकार

दिसंबर 2022 के बाद से स्मॉलकैप इंडेक्स में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। यह 5% गिर गया जबकि मिडकैप में 3% की गिरावट आई। वहीं, माइक्रोकैप और एसएमई स्टॉक सूचकांकों में लगभग 5इ की गिरावट आई। शेयर बाजार के इस हाहाकार की असल वजह क्या है, आइए समझ लेते हैं।

सेबी चेयरपर्सन का सख्त बयान

दरअसल, शेयर बाजार के ओवरवैल्यूएशन पर सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच ने एक सख्त बयान दिया है। हाल ही में बुच ने कहा कि सेबी को छोटे और मध्यम उद्यम (एसएमई) कैटेगरी के शेयर कीमतों में हेराफेरी के संकेत मिल रहे हैं। बुच ने निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा कि यह हेराफेरी आईपीओ और सामान्य रूप से शेयरों की खरीद-बिक्री, दोनों में है। सेबी चेयरपर्सन बुच ने कहा- हमारे पास इस बारे में पता लगाने की तकनीक है। हम कुछ पैटर्न देख रहे हैं। मैं कहूंगी कि यह अभी शुरुआती चरण में है और बात बहुत आगे नहीं बढ़ी है।

बुच ने कहा कि अगर कुछ गलत मिला, तो इस पर एडवाइजरी जारी की जा सकती है। सेबी चेयरपर्सन के इस बयान के बाद निवेशक अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि शेयरों में बिकवाली बढ़ी है। बता दें कि पिछले महीने म्यूचुअल फंडों से बाजार में बढ़ते हाइप को लेकर भी सेबी ने चिंता जाहिर की थी। सेबी ने स्मॉलकैप और मिडकैप निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए एक प्रणाली बनाने के संकेत दिए थे।

बाजार में मुनाफावसूली बीते कुछ समय से शेयर बाजार की तेजी देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा था कि एक बार फिर मुनाफावसूली दिख सकती है। ऐसे में निवेशकों को बाजार के लिए एक करेक्शन की उम्मीद थी।

महादेव ऐप घोटाले का लिंक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के दौरान शेयर बाजार से लिंक का पता लगाया है। ईडी ने दुबई स्थित कथित हवाला ऑपरेटर हरि शंकर टिबरेवाला से जुड़े डीमैट खातों में मौजूद 1,100 करोड़ रुपये के शेयर जब्त कर लिए हैं। ईडी ने दुबई स्थित कथित हवाला ऑपरेटर हरि शंकर टिबरेवाला, एलकेपी फाइनेंस आदि से जुड़े डीमैट खातों में मौजूद 1,100 करोड़ रुपये के शेयरों को जब्त कर लिया है।

US फेड की ब्याज कटौती की पहेली

फरवरी में अमेरिकी मुद्रास्फीति उम्मीद से अधिक बढ़ गई, जिससे चिंता बढ़ गई कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती में देरी हो सकती है। इससे डॉलर इंडेक्स को मजबूती मिली और यहां तक कि अमेरिकी शेयर बाजार में भी उछाल आया। हालांकि, घरेलू बाजार इसे नकारात्मक रूप से देखता है क्योंकि लंबे समय तक हाई इंटरेस्ट रेट भारत जैसे बाजारों में विदेशी पूंजी फ्लो को रोक सकती हैं। इससे निवेशक टेंशन में हैं।

महंगाई के आंकड़े में सरप्राइज नहीं

फरवरी के लिए भारत की खुदरा मुद्रास्फीति में सुधार नहीं दिखा और यह पिछले महीने के स्तर के करीब आ गई, जबकि जनवरी के लिए फैक्ट्री आउटपुट उम्मीद से कमजोर आए। भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति फरवरी 2024 में चार महीने के निचले स्तर 5.09 प्रतिशत पर आ गई, जो जनवरी में 5.1 प्रतिशत थी, जबकि भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि जनवरी में 3.8 प्रतिशत पर स्थिर रही।

मार्च का फैक्टर

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मार्च वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना है। इस महीने में कुछ खास तरह के निवेशक मुनाफावसूली पर जोर देते हैं। श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मुख्य निवेश अधिकारी अजीत बनर्जी ने कहा कि वित्तीय वर्ष करीब होने के कारण कुछ मुनाफावसूली हो रही है। कई कॉर्पोरेट और संस्थागत निवेशक वित्तीय वर्ष के अंत में अपनी बैलेंस शीट पर लाभ दिखाने के लिए मार्च में इक्विटी में अपनी स्थिति समाप्त कर देते हैं। इसके अलावा, मार्च एडवांस टैक्स के भुगतान की समय सीमा है इसलिए कुछ कॉर्पोरेट और निवेशक नकदी जुटाने के लिए इक्विटी बेचने का विकल्प चुन सकते हैं।

बिजली क्षेत्र की डिमांड को पूरा करेगा कोयला मंत्रालय

2024-25 में आयात घटने से एक साल में बचे रु. 82,264 करोड़

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बुधवार को कहा कि कोयला मंत्रालय वित्त वर्ष 2024-25 में बिजली क्षेत्र की 87.4 करोड़ टन कोयले की मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। 31 मार्च को खत्म होने वाले वित्त वर्ष के लिए बिजली मंत्रालय ने 82.1 करोड़ टन की मांग रखी थी। पीटीआई की खबर के मुताबिक जोशी ने बुधवार को 'कोयला क्षेत्र में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान' पुस्तिका के विमोचन के मौके पर यह बात कही। जोशी ने कहा कि बिजली मंत्रालय की मांग पूरी हो गई है।

मार्च तक एक अरब टन कोयला उत्पादन होगा

जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिजली मंत्रालय ने 87.4 करोड़ टन कोयला मांगा है। हम उनकी इस जरूरत को भी पूरा करेंगे। हम इस साल मार्च तक एक अरब टन कोयला उत्पादन के आंकड़े को पार करने जा रहे हैं। जोशी ने कहा कि आयातित कोयले की हिस्सेदारी पिछले वित्त वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष में कम हो गई है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में मिश्रण के लिए कोयले का आयात लगभग 2.22 करोड़ टन था, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 3.08 करोड़ टन था।

82,264 करोड़ रुपये की बचत

जोशी ने कहा कि कोयला आयात में कमी से सिर्फ एक साल में 82,264 करोड़ रुपये की बचत हुई है। सरकार का लक्ष्य 2026 तक कोयले का आयात 'शून्य' करने का भी है। जोशी ने कहा कि कोयला मंत्रालय रैक की उपलब्धता के लिए रेल मंत्रालय के साथ भी संपर्क में है। मंत्री ने कहा कि कोयले के परिवहन के लिए रैक की औसत उपलब्धता भी पिछले वित्त वर्ष में 369 रैक प्रतिदिन से बढ़कर अब 392 रैक प्रति दिन हो गई है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी रैक की उपलब्धता में सुधार होगा। भारत में बिजली उत्पादन में कोयला सबसे बड़ा माध्यम है।

मध्यप्रदेश में एक अप्रैल से सभी औद्योगिक एवं असंगठित श्रमिकों को 25 प्रतिशत अधिक मजदूरी

मजदूरों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार- श्रम मंत्री

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

मध्यप्रदेश में एक अप्रैल से सभी औद्योगिक एवं असंगठित श्रमिकों को 25 प्रतिशत अधिक मजदूरी मिलेगी। सभी औद्योगिक एवं असंगठित क्षेत्र से जुड़े ट्रेंड-अनट्रेंड श्रमिकों का मेहनताना 1 अप्रैल 2024 से बढ़ जायेगा। राज्य शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 के बाद प्रदेश में पहली बार मजदूरों का मजदूरी का पुनरीक्षण किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन और श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल के प्रयासों से श्रमिकों के कल्याण के लिये की गई ठोस पहल है । श्रम मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मजदूरी दरों में की गई बढ़ोतरी श्रमिकों की जिंदगी में व्यापक बदलाव आयेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन एवं मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में किए जा रहे 'सबके विकास' की कड़ी में श्रमिकों के उत्थान के लिए यह पहल की गई है। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग मजदूरों के कल्याण एवं सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय आने वाले समय में भी लिए जाएंगे। नियम अनुसार प्रति 5 वर्ष मंह वेज रिवीजन होना चाहिए, 2014 के बाद पहली बार श्रमिकों का वेज रिवाइज किया है। आगे भी नियमानुसार वेज रिवीजन किया जायेगा।

महिला श्रमिकों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने में मिल का पत्थर साबित होगा। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि भोपाल जिले में संबल योजना अनुचित तरीके से लाभ देने की जानकारी प्राप्त होने पर त्वरित रूप से मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश दिए है। भुगतान की गई राशि के वसूली के लिए भी उचित कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं।

श्रमिकों को मिलेगा महंगाई भत्ता जोड़कर न्यूनतम वेतनश्रमिकों को देय प्रचलित न्यूनतम वेतन की दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि और जनवरी से जून 2019 के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर दिनांक 1 अक्टूबर 2019 से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को न्यूनतम वेतन में जोड़कर नई न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की गई हैं। यह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 पर आधारित कर संबंद्ध की गई है। नई न्यूनतम वेतन दरों के प्रभावशील होने पर अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 9 हजार 575 रुपए प्रतिमाह हो जाएगा। इसी तरह अर्द्धकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 10 हजार 571 रुपए प्रतिमाह होगा। कुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 12294 जबकि उच्च कुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 13919 रुपए प्रतिमाह हो जाएगा। श्रमिकों की वेतन दरें लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जनवरी 2019 से जून 2019 के आंकड़ों के औसत पर आधारित है।

कृषि श्रमिकों को मिलेंगे अब हर महीने 7660 रुपए कृषि श्रमिकों को देय प्रचलित न्यूनतम वेतन की दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि तथा लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के आधार पर 1 अक्टूबर 2019 से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को न्यूनतम वेतन में जोड़कर नई न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की गई है। नई न्यूनतम वेतन दरों के प्रभावशील होने पर कृषि श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 7660 रुपए प्रतिमाह हो जाएगा। इसी प्रकार बीड़ी श्रमिकों एवं अगरबत्ती श्रमिकों के वेतन में भी देय प्रचलित न्यूनतम वेतन की दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। न्यूनतम वेतन की दरें किसी भी श्रमिक पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगी। वर्तमान वेतन की दरें संशोधित दरों से अधिक है तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जाएंगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दरें उसके समकक्ष नहीं हो जाती हैं।

पेटीएम पर 15 मार्च के बाद नहीं कर पाएंगे फास्टैग रिचार्ज

एजेंसी

Paytm पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई रोक लगाई हैं। अब 15 मार्च से इसी कड़ी में बदलाव होने जा रहे हैं। अब पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से कोई नया डिपॉजिट नहीं लिया जा सकता है। हालांकि 15 मार्च से ये सभी बदलाव होने जा रहे हैं। आपको पहले ही बता दें कि केंद्रीय बैंक की तरफ से पहले ही पेटीएम पेमेंट बैंक पर कई रोक लगाई गई हैं। हालांकि इससे पहले ही पेटीएम की तरफ से साफ कर दिया गया है कि यूपीआई पेमेंट पर इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Paytm को लेकर आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐप पहले की तरह ही काम करती रहेगी। अगर आपका बैंक अकाउंट किसी अन्य बैंक में है तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। क्योंकि इसकी मदद से आप आसानी से यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप नॉर्मल पेटीएम का यूज करते हैं वैसे ही करते रहेंगे।

Jio की एंट्री

Jio को लेकर भी इस बीच बड़ी खबर सामने आई है। मुकेश अंबानी भी यूपीआई मार्केट में धमाकेदार एंट्री कर सकते हैं। जियो पे के साथ वह पेटीएम, फोन पे और गूगल पे जैसे ऐप्स को कड़ी टक्कर देने की प्लानिंग कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने नया प्लान भी बनाया हुआ है। जियो बॉक्स की इसको लेकर ट्रायल भी चल रहा है। एक बार पास होने के बाद बहुत जल्द बाजार में जियो पे साउंड बॉक्स की एंट्री होने वाली है। कंपनियों की नजर मार्केट पर-भारत में यूपीआई की मार्केट बहुत बड़ी है। पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगने वाली रोक के बाद सबको लग रहा था कि पेटीएम ऐप बंद होने वाली है। लेकिन पेटीएम की तरफ से लगातार इस पर सफाई भी दी जा रही है। इस बीच कई अन्य कंपनियां इस मौके का इस्तेमाल करना चाहती हैं। यही वजह है कि वह इस पर काफी तेजी से काम भी कर रही हैं। हालांकि अभी तक जियो की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है।

भारत शीघ्र होगा प्रदूषण मुक्त

IIT Bhilai ने खोजा अनोखा तरीका

उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं से प्लास्टिक तैयार

भिलाई। एजेंसी

उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं वातावरण को दूषित करता है, लेकिन जल्द ही इस धुएं से कार्बन डाईऑक्साइड को अलग कर इससे प्लास्टिक तैयार किया जाएगा। आईआईटी भिलाई ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। प्रोजेक्ट को लेकर हाल ही में आईआईटी भिलाई ने विभिन्न सरकारी-गैर सरकारी संस्थानों के साथ एमओयू साइन किया है।

आसानी से हो सकेगा नष्ट

इस प्रोजेक्ट के समन्वयक आईआईटी भिलाई के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. संजीब बैनर्जी ने बताया कि धुएं से कार्बन को अलग करने प्रोटोटाइप तैयार है। शुरुआती रिसर्च के आधार पर देखा गया है कि हवा में घुली कार्बन डाईआक्साइड को प्रोसेस करने पर विशेष प्लास्टिक मिलता है। आमतौर पर प्लास्टिक करीब 500 साल तक नष्ट नहीं होता, लेकिन कार्बन को फिल्टर कर निकाला गया बायोडिग्रेडबल लेवल का प्लास्टिक आसानी से नष्ट किया जा सकता है।

बनाएंगे बीपीए फ्री प्लास्टिक

आईआईटी के प्रोफेसरों ने बताया कि वातावरण से कार्बन डाईआक्साइड को अलग कर बीपीए फ्री प्लास्टिक भी तैयार करने पर रिसर्च तेजी से चल रही है। इसके अलावा हैल्थ सेक्टर में अभी जो बीपीए फ्री प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह काफी महंगा है। हैल्थ सेक्टर की कॉस्ट में कमी लाने के लिए आईआईटी बीपीए फ्री सस्ता प्लास्टिक बनाने तैयारी कर रहा है।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शुरुआत

इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले आईआईटी भिलाई के साथ मध्यप्रदेश के वातावरण पर रिसर्च करेगा। आबोहवा में घुली कार्बन की मात्रा का पता लगाया जाएगा। इसके बाद धुएं को एकत्रित करने के लिए वहीं विशेष चैंबर तैयार किए जाएंगे, जिसको प्रोसेस कर प्लास्टिक मिलेगा। वर्तमान प्रदूषण इंडेक्स के हिसाब से मध्यप्रदेश में इस समय वायुमंडल में सर्वाधिक कार्बन डाईआक्साइड मौजूद है। वहीं इंडस्ट्रीज और गाडियों से निकलने वाले धुएं की मात्रा भी एमपी में सीजी की तुलना में अधिक है। बहरहाल, रिसर्चर दोनों ही राज्यों के वातावरण का अध्ययन कर जगह का चुनाव करेंगे।

कार्बन फुटप्रिंट कम होगा

आईआईटी भिलाई ने सोमवार को हेल्थ केयर और ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत संस्था कैलीच के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत अब दोनों ही संस्थान कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और हैल्थ केयर सेक्टर को सस्टेनेबल बनाने की दिशा में काम करेंगे। इस एमओयू के दौरान आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर डॉ. राजीव प्रकाश, डीन (आरएंडडी) प्रोफेसर संतोष विश्वास, कैलीच के सीईओ अमित प्रियदर्शन ने हस्ताक्षर किए।

देश में शुरू हुई नई एयरलाइन फ्लाय 91

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में नई क्षेत्रीय एयरलाइन शुरू हुई है। इसका नाम Fly91 है। मंगलवार को सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। गोवा के मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (MOPA) से लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप के लिए इसने उड़ान भरी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले एक दशक में नई क्षेत्रीय एयरलाइनों के सामने आने के कारण एविएशन इंडस्ट्री को बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, 'पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस उद्योग में नया युग आया है। इसके कारण छह नई क्षेत्रीय एयरलाइनों का जन्म हुआ है।'

मंत्री ने पीएम मोदी के नेतृत्व में उद्योग के विकास पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि जो एयरलाइन कभी बंद हो रही थीं वे विस्तार की ओर कदम बढ़ा रही हैं। उन्होंने भारत में नागरिक उड्डयन के विकास पर भी जोर दिया। इसमें उन्होंने सरकार की उड़ान स्कीम का जिक्र किया। स्कीम के जरिये सरकार छोटे शहरों को जोड़ रही है।

क्या है टारगेट?

विमानन उद्योग का लक्ष्य 2030 तक घरेलू यातायात को 30 करोड़ तक बढ़ाना है। जबकि 2014 में यह केवल 6 करोड़ था। 18 मार्च से Fly91 की शेड्यूल्ड फ्लाइट शुरू होंगी। ये मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, गोवा और बेंगलुरु, हैदराबाद, जलगांव, अगत्ती, पुणे, नांदेड़ और सिंधुदुर्ग सहित विभिन्न शहरों के बीच संचालन करेंगी।

10 लाख जॉब्स, 100 अरब डॉलर का निवेश और सस्ते होंगे यूरोपीय प्रोडक्ट्स

India-EFTA डील के मायने

नई दिल्ली। एजेंसी

16 वर्षों का लंबा इंतजार आखिर खत्म हो गया है। भारत और यूरोप के 4 देशों के बीच बड़ी डील हुई है। यह है- फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता। अगर आप यूरोपियन प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं और स्विस घड़िया-चॉकलेट्स आदि पसंद करते हैं, तो इस डील से ये वस्तुएं अब आपको कम दाम में मिल जाएंगी। साथ ही यूरोप के इन 4 देशों में आपको खूब भारतीय उत्पाद देखने को मिल सकेंगे। भारत ने जिस संगठन के साथ यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, इसे यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन (EFTA) के नाम से जानते हैं। इस ग्रुप में 4 देश हैं- स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन। ये वे देश हैं, जो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं हैं। आइए जानते हैं कि 16 वर्षों में 21 दौर की वार्ता के बाद हुई इस डील से भारत को क्या फायदा होगा।

गेम चेंजर, अभूतपूर्व और विन-विन सोल्यूशंस

इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भारत सहित इन चारों देशों के अधिकारी गेम-चेंजर, अभूतपूर्व और विन-विन सोल्यूशंस बता रहे हैं। इन चार छोटे यूरोपीय देशों ने अगले 15 वर्षों में भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश करने और 10 लाख से अधिक रोजगार पैदा करने में मदद करने का कमिटमेंट किया है। इससे इन पांचों देशों को फायदा होगा, क्योंकि भारत इस समय दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश के साथ एक काफी बड़ा मार्केट है। हमारे देश में मिडिल क्लास लगातार बढ़ रहा है। साथ ही भारत बड़े देशों में सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बना हुआ है। ऐसे में भारत में निवेश कर हर कोई मुनाफा कमाना चाहता है।

भारत में सस्ते हो जाएंगे यूरोपीय प्रोडक्ट्स

इस निवेश के जवाब में भारत ने कहा है कि वह सोने को छोड़कर 95.3% औद्योगिक आयात पर अभी लग रहे काफी अधिक सीमा शुल्क को तुरंत या धीरे-धीरे हटा देगा या बहुत कम कर देगा। इससे यूरोपीय प्रोडक्ट्स भारत में सस्ते हो जाएंगे और उनकी खपत बढ़ेगी। भारत और चार EFTA देशों को अब इस समझौते को लागू करने से पहले इसे अनुमोदित करने की आवश्यकता है, स्विट्जरलैंड अगले साल तक ऐसा करने की योजना बना रहा है। भारत और ईएफटीए के बीच होने वाले व्यापार में स्विट्जरलैंड का लगभग 91 फीसदी हिस्सा है।

मेक इन इंडिया को मिलेगी रफ्तार

पीएम मोदी ने इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ऐतिहासिक मोड़ बताया है। इस डील से आईटी, व्यापार सेवाओं, शिक्षा, दवाइयां, कपड़ा, रसायन और मशीनरी जैसे सेक्टर्स में निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन मुख्य फोकस इन्वेस्टमेंट पर है। सरकारी अधिकारियों का मानना है कि यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पीएम मोदी की 'मेक इन इंडिया' पहल को रफ्तार देगा। यह पहल विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, रेलवे और फाइनेंशियल सेक्टर्स में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए है। सरकार को उम्मीद है कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स के लिए चीन के विकल्प के रूप में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की बढ़ती अपील का लाभ उठाकर कई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। भारत ने 2021 के बाद से अब तक 4 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किये हैं। भारत और ईएफटीए पहले यूरोपीय फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं। भारत यूके, यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए चर्चा कर रहा है।

ये सामान हो जाएंगे सस्ते

भारत ईएफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से स्विस घड़ियां, फार्मा प्रोडक्ट, फर्टीलाइजर्स, चॉकलेट,

मिनरल्स, टेक्सटाइल्स, स्मार्टफोन, आयरन और स्टील प्रोडक्ट देश में सस्ते हो जाएंगे। अभी भारत में स्विस घड़ियों पर 20 फीसदी और यूरोपीय चॉकलेट पर 30 फीसदी इंफोर्ट ड्यूटी लगती है। इसके अलावा सीफूड, मेडिटेरेनियन फल, कॉफी, तेल, मिठाइयां, प्रोसेस्ड फूड और शराब की कीमतों भी कम हो जाएंगी।

घटेगा भारत का व्यापार घाटा

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के प्रमुख व्यापार अर्थशास्त्री राम सिंह ने रॉयटर्स को बताया, 'यह व्यापार समझौता स्विट्जरलैंड और नॉर्वे की टेक्नोलॉजीज तक पहुंच बनाकर मेडिकल डिवाइसेज और क्लीन एनर्जी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने और अन्य देशों को निर्यात बढ़ाने में मदद करेगा।' विश्लेषकों का कहना है कि EFTA समझौता भारत को EFTA के साथ अपने बड़े व्यापार घाटे को कम करने में तुरंत मदद नहीं कर सकता है, लेकिन यह प्रमुख उद्योगों में निवेश आकर्षित करने में मदद करेगा। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत और इन देशों के बीच 18.65 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। लेकिन इसमें भारत का व्यापार घाटा 14.8 अरब डॉलर रहा था।

इस साल वैश्विक व्यापार में आएगी तेजी, बढ़ रहा है कॉरपोरेट ग्लोबलाइजेशन : रिपोर्ट

नई दिल्ली। एजेंसी

कोविड-19 महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध, गाजा में युद्ध और अमेरिका-चीन व्यापार विवाद के बीच ग्लोबलाइजेशन 2022 में पिछले दशक की तुलना में रिकॉर्ड उच्चस्तर पर पहुंच गया और 2023 में भी यह ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। एक रिपोर्ट में बुधवार को यह बात कही गई है। डीएचएल और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा जारी 'न्यू डीएचएल ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट-2024' में यह भी कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार वाले वैश्विक उत्पादन का हिस्सा 2022 में रिकॉर्ड उच्चस्तर पर फिर वापस आ गया है।

इस साल व्यापार में ग्रोथ आने का अनुमान

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में सुस्ती के बाद 2024 में व्यापार वृद्धि में तेजी आने का अनुमान है। व्यापार वृद्धि ने संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रिपोर्ट में व्यापार के प्रवाह, पूंजी, सूचना और लोगों की आवाजाही का आकलन किया गया है। यह दुनिया के 181 देशों और क्षेत्रों के वैश्वीकरण को मापती है। पिछले दो दशक में सूचना प्रवाह के वैश्वीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, भले ही ताजा आंकड़े इनकी वृद्धि में सुस्ती के रुख को दिखाते हैं। इसकी वजह अमेरिका और चीन के बीच अनुसंधान को लेकर कम सहयोग है।

बढ़ रहा कॉरपोरेट ग्लोबलाइजेशन

रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। कंपनियां अपनी अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति बढ़ा रही हैं और विदेशों में अधिक बिक्री कारोबार अर्जित कर रही हैं। डीएचएल एक्सप्रेस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी जॉन पियर्सन ने कहा, ''डीएचएल ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट' के हालिया निष्कर्ष स्पष्ट रूप से वैश्वीकरण के रुख के पलटने की धारणा को खारिज कर देते हैं। आज ग्लोबलाइजेशन सिर्फ चर्चा का कारण नहीं है, बल्कि एक प्रभावशाली शक्ति है, जिसने हमारी दुनिया को गहराई से नया आकार दिया है और इसमें और भी बड़ी संभावनाएं हैं।''

यामाहा ने तीन नए 'ब्लू स्क्वैयर' आउटलेट खोले

आईपीटी नेटवर्क

इंडिया यामाहा मोटर (आइवाईएम) प्राइवेट लिमिटेड ने तीन नए अत्याधुनिक 'ब्लू स्क्वैयर' आउटलेट खोलने की घोषणा की। इन नए यामाहा एक्सक्लूसिव आउटलेट्स को मोती नगर में 3,266 वर्गफुट में 'एक्सीलेन्स मोटर्स एलएलपी', गणेश नगर में 3,086 वर्गफुट में 'अम्बुज ऑटोमोबाइल्स', और कृष्णा नगर में 2,300 वर्गफुट में 'प्राइम ऑटोमेशन' के नाम से लॉन्च किया गया है। नए ब्लू स्क्वैयर आउटलेट्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे कि ग्राहकों को एक बेहद व्यक्तिगत नजरिये के जरिये शुरू से लेकर अंत तक बिक्री, सेवा और सहायता में बेहतर अनुभव प्राप्त हो सके। यामाहा ब्लू स्क्वैयर आउटलेट्स ब्रांड की वास्तविक भावना को दिखाते हैं और इन्हें ग्राहकों को शुरू से लेकर अंत तक बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए काफी सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया है। ये आउटलेट्स एक व्यक्तिगत नजरिये की मिसाल है और यहाँ यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर ग्राहक को पूरी संतुष्टि मिले और उसे अपनी अहमियत का पूरा अहसास हो। ब्रांड इन एक्सक्लूसिव आउटलेट्स का लाभ उठाकर ग्राहकों के लिए यामाहा रेसिंग में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करना चाहता है। इन प्रीमियम आउटलेट्स का हर सेक्शन काफी सोच-समझकर तैयार किया गया है, यह अंतरराष्ट्रीय मोटरस्पोर्ट्स पर गहरी पकड़ वाले वैश्विक ब्रांड के साथ जुड़े होने के गर्व का अहसास कराना चाहते हैं। इस सिद्धान्त से प्रेरित, यामाहा ने ब्लू और स्क्वैयर के संयोजन के साथ ग्राहकों से फौरन संबंध स्थापित किया है। इस संयोजन में 'ब्लू' इस ब्रांड की गौरवशाली रेसिंग विरासत को दर्शाता है, जबकि 'स्क्वैयर' यामाहा की रोमांचक, स्पोर्टी और स्टाइलिश टू-व्हीलर रेंज के साथ ग्राहकों के जुड़ने के लिए एक क्यूरेटेड प्लैटफॉर्म का प्रतीक है।

वनस्पति तेल आयात में आई बड़ी गिरावट

फरवरी में घटकर हो गया इतना, भारत ने मंगाया 9,74,85 टन

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश में विदेश से वनस्पति तेल के आयात के आंकड़ों में गिरावट आई है। भारत ने फरवरी में सालाना आधार पर 13 प्रतिशत से कम लगभग 9.75 लाख टन ही वनस्पति तेल आयात किया है। उद्योग के आंकड़ों से बुधवार को यह जानकारी मिली है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) ने बयान में कहा कि फरवरी के दौरान

वनस्पति तेलों (खाद्य तेलों और गैर-खाद्य तेलों सहित) का आयात 9,74,85 टन रहा, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 11,14,481 टन था। कुल आयात में खाद्य तेल का हिस्सा घटकर 9,67,852 टन रह गया। फरवरी, 2023 में यह 10,98,475 टन था।

एक साल में कुल आयात

खबर के मुताबिक, गैर खाद्य तेलों का आयात भी एक साल पहले की समान अवधि के 16,006 टन से घटकर 7,000 टन रह गया। नवंबर, 2023-फरवरी, 2024 की अवधि के दौरान, वनस्पति तेलों का कुल आयात 21 प्रतिशत घटकर 46,47,963 टन रह गया, जो पिछले तेल वर्ष की इसी अवधि में 58,87,900 टन था। तेल मार्केटिंग वर्ष नवंबर से अक्टूबर तक चलता है। तेल वर्ष 2023-24 के पहले चार माह के दौरान खाद्य तेलों का आयात घटकर 46,15,551 टन रह गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 58,44,765 टन था।

50% से अधिक घरेलू जरूरत आयात से होता है पूरा

तेल वर्ष 2023-24 की नवंबर-फरवरी अवधि के दौरान गैर-खाद्य तेलों का आयात घटकर 32,412 टन रह गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 43,135 टन था। भारत खाद्य तेलों की अपनी 50 प्रतिशत से अधिक घरेलू जरूरत को आयात से पूरा करता है। भारत द्वारा इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम तेल का आयात किया जाता है। यह अर्जेंटीना और ब्राजील से सोयाबीन तेल का आयात करता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि फरवरी, 2024 में वनस्पति तेल के आयात में गिरावट जारी रही। खाद्य तेल आवश्यकताओं के लिए पाम तेल की उपलब्धता में कमी आई है क्योंकि मुख्य दो उत्पादक देश मलेशिया और इंडोनेशिया इसे बायोडीजल के उत्पादन के लिए लगा रहे हैं।

18 साल बाद राहु-बुध की महायुति

इन राशिवालों की धन-दौलत में होगी बढ़ोतरी

पं. राजेश वैष्णव
शनि उपासक ज्योतिष रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ
98272 88490

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, ग्रह समय-समय पर गोचर करते हैं और अन्य ग्रहों के साथ युति बनाते हैं। कुछ दिनों पहले बुध ग्रह ने मीन राशि में प्रवेश किया है। जहां छाया ग्रह राहु पहले से विराजमान है। इन दोनों ग्रहों ने मीन राशि में युति बनाई है। यह महागठबंधन 18 साल बाद बना है। राहु और बुध की युति 25 मार्च तक रहेगी। इस दौरान कुछ राशियां बेहद भाग्यशाली रहेंगी।

कर्क राशि

राहु और बुध की युति कर्क राशिवालों के लिए लाभकारी हो सकती है। आय के स्त्रोत बढ़ने की संभावना है। रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। सरकारी काम पूरा हो सकता है। नई नौकरी पाने में सफलता मिल सकती है।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु और बुध का मिलन शुभ फलदायी हो सकता है। पैतृक संपत्ति से आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आय के अधिक स्त्रोत मिल सकते हैं। एक के बाद एक कई काम पूरे करने में सफल हो सकते हैं। व्यापार में नए मौके मिल सकते हैं।

मकर राशि

राहु और बुध का मिलन मकर राशिवालों के लिए शुभ दिन ला सकता है। नौकरीपेशा जातकों मेहनत का फल मिलेगा। व्यापारियों को निवेश से भारी मुनाफा हो सकता है। करियर में सुनहरे मौके मिल सकते हैं। कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

वास्तु शास्त्र के अनुसार इन रंगों से खेलें होली, मिलेंगे सकारात्मक परिणाम

डॉ. संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

होली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग सभी बैर भूलकर एक-दूसरे को रंग लगाते हैं। होली के त्योहार का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, रंगों से होली खेलने के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। माना जाता है कि इन उपायों को अपनाया जाए, तो जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। आज हम आपको होली से जुड़े वास्तु के कुछ विशेष नियम बताने जा रहे हैं। इनसे आपका होली का त्योहार खुनशुना बन जाएगा।

उत्तरमुखी घर है, तो इन रंगों से खेले होली

वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर आप घर पर परिवार और दोस्तों के साथ होली मना रहे हैं, तो होली खेलते समय दिशाओं का ध्यान रखें। यदि आपके घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में खुलता है, तो आपका घर उत्तरमुखी है। उत्तर मुखी घर में होली खेलने के लिए पीला, हरा, नीला और हल्का नीला रंग अच्छा माना जाता है। इन रंगों से होली खेलने से जीवन की वर्तमान परेशानियों से छुटकारा मिलता है। साथ ही सकारात्मक ऊर्जा आती है।

दक्षिणमुखी घर है, तो इन रंगों से खेले होली

यदि आपका घर दक्षिण दिशा की ओर है, तो आपको गुलाबी, बैंगनी, नारंगी और लाल रंग से होली खेलनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार, इससे परिवार के सदस्यों का आत्मविश्वास बढ़ता है और आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है।

पूर्वमुखी घर है, तो इन रंगों से खेले होली

अगर आपका घर पूर्व दिशा की ओर है, तो घर में होली खेलते समय आपको गहरे रंग जैसे पीला, लाल, हरा, गुलाबी और नारंगी रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। इन रंगों से होली खेलने से मान-सम्मान वृद्धि होती है। वहीं, अगर आपका घर पश्चिम दिशा की ओर है, तो आपको होली खेलने के लिए हल्के नीले, सुनहरे या सफेद रंग का उपयोग करना चाहिए। माना जाता है कि इससे जीवन में सुख-शांति बनी रहती है।

इन राशि वालों के लिए बेहद अशुभ रहेंगे होलाष्टक, हो सकता है बड़ा नुकसान

डॉ. आर.डी. आचार्य
9009369396
ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
इंदौर (म.प्र.)

इस बार होली का त्योहार 25 मार्च को मनाया जाने वाला है। इससे पहले 17 मार्च से होलाष्टक शुरू होने जा रहे हैं, जो कि 8 दिन तक रहेंगे। होलाष्टक में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस साल होलाष्टक में शनि, सूर्य और राहु कुछ राशि वालों के लिए अशुभ रहने वाले हैं। 18 मार्च को शनि उदय होंगे। कुंभ राशि में शनि का उदय हो रहा है, जिसका असर सभी राशियों पर पड़ने वाला है। वहीं, 14 मार्च को सूर्य गोचर करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि में पहले से ही राहु विराजमान हैं। मीन राशि में सूर्य और राहु की युति से ग्रहण योग बनने जा रहा है। यह ग्रहण योग ज्योतिष में काफी अशुभ माना जाता है। इस समय मकर, कुंभ और मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है। इसके कारण शनि, सूर्य और राहु का बुरा प्रभाव कुछ राशि पर पड़ेगा।

मकर राशि

होलाष्टक पर ग्रहों की स्थिति का मकर राशि वालों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस समय अवधि में आपको कई क्षेत्रों में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। खर्चों को लेकर थोड़ा सावधान रहें। जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इस दौरान आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों को होलाष्टक के दौरान किसी प्रकार की हानि हो सकती है। आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। छात्रों के लिए यह समय उत्तम माना गया है। किसी यात्रा पर जा सकते हैं। व्यापार में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है।

मीन राशि

मीन राशि वालों को होलाष्टक के दौरान मानहानि हो सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

जिंदगी के जरूरी फैसले लेते समय रखें इन 4 बातों का ध्यान, कभी नहीं होगा पछतावा

श्रीमती नीतू मित्तल
8959760040
ज्योतिषाचार्य, इंदौर (म.प्र.)

जीवन की राह में आगे बढ़ने के लिए हमें कई बार महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ते हैं. हालांकि सही फैसला लेना कोई आसान काम नहीं होता है. कई बार हमारी छोटी सी लापरवाही हमारे फैसलों पर भारी पड़ जाती है. एक गलत निर्णय की वजह से हमें जीवन भर पछताना पड़ जाता है. आइए जानते हैं कि जिंदगी के जरूरी फैसले लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

भावनाओं में आकर फैसला न लें

किसी भी निर्णय को लेते समय अपनी भावनाओं को काबू में रखें. भावनाओं में बहकर लोग अक्सर सही-गलत का चुनाव नहीं कर पाते हैं. भावनाओं में लिए गए फैसले अक्सर आगे चलकर गलत साबित होते हैं. इसलिए जिंदगी के जरूर फैसले लेते समय भावनाओं के साथ-साथ अपने दिमाग की बात भी सुनें. अपना फायदा-नुकसान देखते हुए ही कोई फैसला लें.

बड़ों की राय लें

मुश्किलें आने पर अक्सर लोग घबरा जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता है कि आगे अब क्या करें. ऐसे में हमारे बड़े-बुजुर्गों के अनुभव हमारे काम आ सकते हैं. आप दिल की बात उनसे शेयर कर उनसे सलाह ले सकते हैं. इससे आपको कोई भी बड़ा फैसला लेने में आसानी होगी. आप चाहें तो कोई निर्णय लेने से पहले दोस्तों से भी राय ले सकते हैं. इससे आप भ्रमित होने से बच जाएंगे.

फैसले के परिणाम के बारे में सोचें

कोई भी निर्णय लेते समय उसके परिणाम के बारे में अच्छे से सोच लें. इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि उस निर्णय से आपको तुरंत फायदा हो रहा है या बाद में फायदा हो रहा है. कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिन्हें लेने के बाद कुछ समय का दुख होता है लेकिन आगे चलकर यह हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होते हैं. यह फैसले हमारे करियर या फिर पर्सनल लाइफ दोनों से जुड़े हो सकते हैं.

दूसरी योजना तैयार रखें

एक सही फैसला लेते समय कई सारे जोखिम भी होते हैं. जरूरी नहीं कि आपका हर निर्णय सही साबित हो. अगर आपको कोई निर्णय सही नहीं निकलता है तो इसे भी आपको स्वीकार करना होगा. अपने हर निर्णय का एक बैकअप प्लान भी तैयार रखें. निर्णय लेते समय यह बात पहले ही सोच लें कि अगर ये फैसला गलत हो गया तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं. इस तरह से आप अपने निर्णय के परिणाम के लिए मानसिक रूप से तैयार रहेंगे.

डिश टीवी की केबल टीवी इंडस्ट्री में जान फूंकने की बड़ी पहल

'ओन योर कस्टमर' लॉन्च

नई दिल्ली। एजेंसी

डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) टेलीविजन सेवाओं में अग्रणी डिश टीवी इंडिया ने केबल ऑपरेटर्स के साथ की गई साझेदारी के तहत एक अभूतपूर्व पहल 'ओन योर कस्टमर' (ओवाईसी) शुरू की है। डिश टीवी इस पहल में स्थानीय केबल ऑपरेटर्स (एलसीओ) के साथ साझेदारी के जरिए ऑप्टिकल फाइबर, ट्रांसमीटर, नोड्स और एम्प्लीफायर्स जैसे व्यापक इन्फ्रास्ट्रक्चर के बिना आसानी से उन्हें ग्राहकों तक टीवी सुविधाएं प्राप्त करा सकेगा। इससे नेटवर्क की विश्वसनीयता बढ़ेगी और इसकी मजबूत कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित होगी।

कोविड महामारी के बाद ओटीटी प्लैटफॉर्म और डीटीएच सर्विस का विस्तार हुआ तो पारंपरिक केबल टीवी सर्विसेज को झटका लगा। ऐसे में डीटीएच की पहल 'ओन योर कस्टमर' (ओवाईसी) केबल ऑपरेटर्स को अपने कस्टमर बेस को मजबूत बनाने में मददगार साबित होने वाली है। किसी भी केबल ऑपरेटर की शक्ति उसका कन्ज्यूमर बेस है। चूंकि केबल ऑपरेटर्स वास्तव में ग्राहकों की घटती संख्या को लेकर चिंतित हैं। डिश टीवी की इस पहल से सभी केबल ऑपरेटर्स को न सिर्फ एक सही समाधान मिलेगा बल्कि उन्हें बिना किसी इन्वेस्टमेंट और सर्विसिंग ओवरहेड्स के अपने ग्राहकों को जोड़े रखने में मदद भी मिलेगी। आज ग्राहक डीटीएच में इसलिए भी ट्रांसफर होना चाहते हैं क्योंकि वे अपने टीवी देखने के अनुभव में किसी भी तरह की रुकावट न महसूस करें। ओवाईसी के साथ लोकल केबल ऑपरेटर्स (एलसीओ) और मल्टीसिस्टम ऑपरेशंस (एमएसओ) को अपने नेटवर्क पर पूरी आजादी मिलती है और अपने संबंधित क्षेत्रों में डिश टीवी के डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम करते हैं। इसके ऑटोमेटेड पोर्टल के जरिए रिचार्ज और एक्टिवेशन पर उनका पूर्ण नियंत्रण रहता है, जिससे बाहरी संस्थाओं पर निर्भरता समाप्त हो जाती है। केबल कन्ज्यूमर अब अपने केबल ऑपरेटर्स की मदद से बेहतर तकनीक का अनुभव कर सकेंगे। एलसीओ के पास अब ब्रॉडबैंड स्थापित करने का अवसर होगा ताकि ग्राहक घर बैठे डिश टीवी एंड्रॉइड बॉक्स जैसी नई डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर सकेंगे। यह एंड्रॉइड बॉक्स एलसीओ की तरफ से दिए गए ब्रॉडबैंड कनेक्शन को और भी मजबूत बनाता है। इसे सेट करने या इसके इस्तेमाल में कोई समस्या होने पर ग्राहक को केवल अपने केबल ऑपरेटर्स से संपर्क करना होगा।

डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के सीईओ मनोज डोभाल 'ओन योर कस्टमर' पहल को लेकर खुशी जताई। उन्होंने कहा, 'हमें 'ओन योर कस्टमर' अभियान को पेश करते हुए खुशी हो रही है, जो मीडिया वितरण में पहली और अनोखी पहल है। यह केबल टीवी वितरण में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। डिश टीवी की मदद से यह पहल एलसीओ और एमएसओ को सशक्त बनाने में पूरी तरह मदद करती है। इस साझेदारी से एलसीओ अपने कन्ज्यूमर बेस बढ़ा सकते हैं और ऑपरेशनल कॉस्ट कम कर सकते हैं, जबकि डिश टीवी नए ग्राहकों तक अपनी पहुंच प्राप्त करता है और सर्विसिंग ओवरहेड्स को कम करता है। यह संबंध यह सुनिश्चित करता है कि दोनों पक्ष ग्राहकों को अद्वितीय मूल्य तथा सेवाएं प्रदान करते हुए पूरी इंडस्ट्री को बदलने को लेकर प्रतिबद्ध है।'

डिश टीवी ओवाईसी के जरिए एलसीओ बिजनसेज के विकास का समर्थन करते हुए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। इसका सीधा उद्देश्य डीटीएच और केबल नेटवर्क, दोनों की ताकत की सहायता से केबल टीवी इंडस्ट्री में फिर से जान फूंकना है। ऐसे में डिश टीवी, एलसीओ और एमएसओ के ग्राहक संबंधों को सशक्त बनाकर उसके विकास को बढ़ावा दे रहा है और टीवी वितरण के लिए एक ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण की शुरुआत भी कर रहा है। ऐसे में डिश टीवी की इस अनोखी पहल ने टेलीविजन वितरण क्षेत्र में ग्राहकों का जरूरी ध्यान खींचा है और उनकी रुचि को आकर्षित किया है, जिससे एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिब्यूशन के भविष्य को नया आकार देने में मदद मिलेगी।

रियलमी 12 सीरीज 5जी मिड-प्रीमियम सेगमेंट में हलचल

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत के सबसे विश्वसनीय स्मार्टफोन सेवा प्रदाता रियलमी ने आज रियलमी 12 सीरीज 5जी पेश की है। रियलमी 12 सीरीज 5जी सीरीज में दो शानदार स्मार्टफोन- रियलमी 12$ 5जी और रियलमी 12 5जी लॉन्च किए गए हैं यह रियलमी के सफर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जो इसकी मेक इट रियल और ब्रांड की एक रिफ्रेश्ड पहचान के अनुरूप है जो यव यूजर्स की जरूरतों से मेल खाती है।

इस लॉन्च के बारे में रियलमी के प्रवक्ता ने कहा आज हमारे सफर का एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि हम आज रियलमी 12 सीरीज 5जी में दो शानदार स्मार्टफोन रियलमी 12ऽ 5जी और रियलमी 12 5जी लेकर आए हैं यह लॉन्च हमारी संशोधित मेक इट रियल रणनीति के अनुरूप है हमारी ब्रांड की रिफ्रेश्ड पहचान युवा यूजर्स से जुड़ाव विकसित करने के लिए डिजाइन की गई है और उन्हें अपनी श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी प्रदान करती है जो उनकी गतिशील जीवनशैली के अनुकूल है ये दोनों स्मार्टफोन हमारी इसी प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं हमारा मानना है कि रियलमी 12 सीरीज 5जी मिड-प्रीमियम सेगमेंट में अद्वितीय मूल्य और प्रदर्शन के साथ हमारी यह प्रतिबद्धता पूरी कर रहा है।'

मीडियाटेक इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर मार्केटिंग और कम्युनिकेशन अनुज सिद्धार्थ ने कहा मेनस्ट्रीम से लेकर फ्लैगशिप सेगमेंट तक सभी स्मार्टफोन को पॉवर मीडियाटेक से मिलती है मीडियाटेक डाइमेंसिटी द्वारा पॉवर्ड नई रियलमी 12 सीरीज 5जी के लिए रियलमी के साथ हमारे सहयोग द्वारा हम अपना ध्यान शानदार टेक्नोलॉजी हर किसी के हाथों में पहुँचाने पर केंद्रित कर रहे हैं मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7050 द्वारा पॉवर्ड रियलमी 12ऽ 5जी में मीडियाटेक मीराविजन डिस्प्ले और वीडियो एन्हांसमेंट, एआई-पॉवर्ड कैमरा, 5जी अल्ट्रासेव, ड्युअल 5जी सिम, बेहतर सीपीयू परफॉर्मेंस और मीडियाटेक हाइपरइंजन गेमिंग टेक्नोलॉजी के साथ स्मूथ गेमिंग अनुभव हैं इसके अलावा हम अपने मौजूदा सहयोग को मजबूत बनाने और नई प्रगति की ओर बढ़ने के लिए आशान्वित हैं।'

ओला इलेक्ट्रिक ने दी नई सौगात

31 मार्च तक अपने एस1 पोर्टफोलियो की कीमत को 25,000 रुपये तक घटाया

बेंगलुरु। आईपीटी नेटवर्क

इलेक्ट्रिक स्कूटर को पसंद करने वालों के लिए एक खुशखबरी, ओला इलेक्ट्रिक ने मार्च महीने के लिए अपने एस 1 स्कूटर पोर्टफोलियो की कीमतों में 25,000 रुपये तक छूट की घोषणा करी है। उनके इस बड़े कदम को उठाने का उद्देश्य भारत के विद्युतीकरण प्रयासों में तेजी लाकर ईवी अपनाने में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करना है। कीमत में कटौती कंपनी की मजबूत कीमत संरचना के साथ-साथ मजबूत एकीकृत इन-हाउस प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षमताओं और विनिर्माण प्रोत्साहन की काबिलियत के कारण हुई।

अब ओला एस1 चाहने वालों के लिए उनकी इच्छा पूरी करने का समय आ गया है, क्योंकि एफएएमई (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) योजना 31 मार्च 2024 को समाप्त होने की संभावना है और ईवी की कीमतों में बड़ा बदलाव हो सकता है। एक आकर्षक कीमत वाले उत्पाद पोर्टफोलियो के साथ ओला एस1 स्कूटर किसी भी पारंपरिक आईसीई वाहन से बेहतर परफॉर्मेंस देता है। इसी वजह से यह स्कूटर हर साल लगभग 30,000 रुपये तक की बचत के साथ बाजार में बेहतर विकल्प बन जाता है।

हाल ही में, ओला इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के तहत घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) प्रमाणपत्र हासिल करने वाली पहली भारतीय 2व्हीलर कंपनी बन गई है। पीएलआई प्रमाणन कंपनी की वर्टिकली एकीकृत विनिर्माण क्षमताओं का सबूत है, जिसने इसकी मजबूत स्थानीयकृत आपूर्ति श्रृंखला इकोसिस्टम और सरकारी सब्सिडी के साथ मिलकर कंपनी को कीमतों को दुबारा तय करने में मदद की है।

ओला इलेक्ट्रिक ने हाल ही में ईवी को अपनाने में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने की कोशिश में उत्पादों, सेवा, चार्जिंग नेटवर्क और बैटरी वारंटी आदि से जुड़ी कई पहलों की घोषणा की है। एस 1 एक्स (4किलोवॉट घंटा) के लॉन्च के साथ - साथ ओला इलेक्ट्रिक ने अपने पोर्टफोलियो को छह सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उत्पादों तक बढ़ाया है, जो अलग-अलग कीमतों पर अलग-अलग रेंज की ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करती हैं।

सैमसंग ने ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वाशिंग मशीन की नई रेंज को लॉन्च किया

11 किलोग्राम एआई इकोबबल TM

गुरुग्राम। एजेंसी

भारत के सबसे बड़े उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड सैमसंग ने आज पूरी तरह से ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वाशिंग मशीन एआई ईकोबबलTM की नई रेंज को लॉन्च कर दिया है। वाशिंग मशीनों की यह नई रेंज 11 किलोग्राम सेगमेंट में पहली है जो एआई वॉश, क्यू-ड्राइवटीएम और ऑटो डिस्पेंस जैसी एडवांस्ड फीचर्स से युक्त है। इसके उपयोग से उपभोक्ताओं को कपड़े धोने में 50% समय की बचत होगी, फैब्रिक की देखभाल पहले की तुलना में 45.5% बेहतर होगी और 70% तक उर्जा की बचत होगी।

एआई ईकोबबलTM सैमसंग की क्यू-बबलऊश और क्विकड्राइवऊश प्रौद्योगिकियों का समागम है, जो धुलाई को अधिक सहज और कम समय लेने वाला बनाता है। Q-बबलTM तकनीक तेजी से डिटर्जेंट प्रवेश के लिए अधिक प्रचुर और शक्तिशाली बुलबुले बनाने के लिए अतिरिक्त पानी के शॉट्स के साथ गतिशील ड्रम रोटेशन को जोड़ती है, वहीं क्विक ड्राइवTM धोने के समय को 50% तक कम कर देता है। ये विशेषताएं एआई इकोबबलTM के प्रदर्शन को बेहतर और टिकाऊ बनाती हैं क्योंकि यह जल और ऊर्जा संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ऑटो डिस्पेंस और एआई वॉश के साथ नई रेंज अत्यधिक सहज और स्मार्ट है। एआई वॉश फीचर कपड़ों का वजन, पानी की मात्रा, कपड़ों की नरमी, मैल की मात्रा और डिटर्जेंट की मात्रा को खुद तय करता है। इससे यह कपड़े जल्दी और अच्छी तरह से धोता है। यह पानी और डिटर्जेंट बचाता है। यह कपड़ों को नुकसान से बचाता है।

सैमसंग इंडिया में डिजिटल एप्लांयसेस बिजनेस के सीनियर डायरेक्टर पुष्प बैशाखिया ने कहा, 'सैमसंग में, हम ऐसी तकनीक पेश करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो न केवल सहज हो बल्कि टिकाऊ भी हो। हमने विभिन्न उपभोक्ताओं की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई रेंज डिजाइन की है। 11 किलोग्राम पूर्ण स्वचालित फ्रंट लोड वाशिंग मशीन सेगमेंट में हमारी पहली रेंज अत्यधिक ऊर्जा कुशल है। ऑटो डिस्पेंस, एआई वॉश और क्यू-ड्राइवTM जैसी सुविधाएं धुलाई को आसान और आसान काम बनाने में योगदान देती हैं।'

मध्य भारत की सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदर्शनी का इंदौर में संपन्न

औद्योगिक विकास के लिए हर संभव प्रयास, एग्जिबिशन सेंटर की जमीन तय, लैंड यूज बदलने के बाद मिलेगी- विजयवर्गीय

इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो में 350 से अधिक कंपनियां हुई शामिल

एक्सपो 2024 के मुख्य आकर्षण

- बड़े मशीन निर्माताओं और कंपनियों द्वारा उत्पादों का प्रदर्शन
- रॉ मटेरियल, पार्ट्स, आदि का प्रदर्शन
- मप्र और अन्य राज्यों से उद्योगपतियों की भागीदारी
- नए उत्पादों और कंपनियों का प्रदर्शन
- परिचर्चा और सम्मान समारोह का आयोजन

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

मध्य भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदर्शनी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो 2024 8 से 11 मार्च 2024 तक लाभ गंगा एग्जिबिशन सेंटर बाईपास के समीप आयोजित किया गया है। एक्सपो का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, मप्र शासन ने किया। इस वर्ष के एक्सपो में मुख्य रूप से बड़े मशीन निर्माता और कंपनियां अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। बड़े मशीन निर्माताओं के इंदौर आने से विजिटर्स को लाइव मशीन डेमों देखने का मौका मिला। विजिटर एक्सपो में बड़ी मशीनों से उत्पाद बनते हुए देख जानकारी ली। इस दौरान 350 स्टॉलों पर रॉ मटेरियल, पार्ट्स, आदि कंपनियों द्वारा प्रदर्शित कर रही है। एक्सपो को इंडियन प्लास्ट पैक फोरम, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मप्र, और बीएनआई के संयुक्त तत्वाधान में फ्यूचर कम्युनिकेशन इंवेट एंड एग्जिबिशन प्रा. लि. द्वारा किया गया।

एक्सपो का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, मप्र शासन ने किया। इस अवसर इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के अध्यक्ष श्री सचिन बंसल, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मप्र के अध्यक्ष योगेश मेहता, वरिष्ठ उद्योगपति, हितेश मेहता, अंकित भरूका,तरूण व्यास, लक्ष्मण दूबे सहित बडी संख्या में उद्योगपति मौजूद थे। श्री विजयवर्गीय ने आयोजन को उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि, प्रदेश शासन औद्योगिक विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्र की अनेक योजनाओं के साथ ही टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में पुनः केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी और देश के विकास को नई दिशा देगी। उन्होंने कहा कि इंदौर में बड़ा एग्जिबिशन सेंटर बनाने की मांग पर कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। अभी जो जमीन देखी है वो कमर्शियल है और उसका लेंड यूज चेंज करवाने में थोडा समय लगेगा। उन्होंने वादा किया कि मेरे 5 साल के कार्यकाल में एक एक्सपो नए एग्जिबिशन सेंटर में जरूर लगेगा। इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के अध्यक्ष श्री सचिन बंसल ने बताया कि इस वर्ष के आयोजन में मुख्य रूप से बडे मशीन निर्माता और कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों का जीवंत प्रदर्शन देखना विजिटर और युवा उद्यमियों के लिए नया अनुभव है। लगभग 350 स्टॉलों पर रॉ मटेरियल, पार्ट्स, आदि कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है। आयोजन में वरिष्ठ उद्योगपतियों से चर्चा, सम्मान समारोह और टॉक शो आदि का आयोजन भी किया जाएगा। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मप्र के अध्यक्ष श्री योगेश मेहता ने बताया कि मप्र के सभी प्रमुख शहरों से उद्योगपतियों का इंदौर आना उद्योग-व्यापार को बढावा देता है। ऐसे आयोजनों में मुंबई, दिल्ली सहित सभी महानगरों से बड़े उद्योग समूह और निर्माता शामिल है। उन्होनें इंदौर में औद्योगिक प्रदर्शनी के आयोजनों को बढ़ाने के लिए शासन से अधिक से अधिक सहयोग की मांग की। बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल इंदौर चेप्टर के प्रमुख श्री आकाश वर्मा ने बताया कि उद्योगों के बडे समूह के रूप मे हम पहली बार एक्सपो में शामिल हो रहे है। इसका लाभ उद्योगों के साथ उपभोक्ताओं को भी होगा। BNI ग्रुप की इंदौर इकाई द्वारा इसमे अलग तरह के 100 से ज्यादा स्टाल लगाए जा रहे। फ्यूचर कम्युनिकेशन इंवेट एंड एग्जिबिशन प्रा. लि. के डायरेक्टर श्री लक्ष्मण दुबे ने बताया कि इस 4 दिवसीय एक्सपो में अनेक ऐसे उत्पाद और कंपनियां शामिल होंगी जो पहली बार टियर-2 शहरों में आई है। देश की मुख्य मशीन बनाने वाली कंपनियों जैसे जयश्री मशीन टूल्स, ज्योति ण्ज, भव्या मशीन टूल्स, मेहता केड केम, लेजर टेक्नोलॉजी, क्रिष्ना शॉट ब्लास्ट, ABK लेजर, महक ण्ज सहित अनेक मशीन निर्माता कंपनियां शामिल हुई है।

पत्रकारिता के मूल्यों को जीवित रखने के लिए आचरण के मानकों का पालन आवश्यक

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों को जीवित रखने और समाज में विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पत्रकारिता के आचरण के मानकों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यह विचार आज इंदौर में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में व्यक्त किए गए। कार्यशाला में वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि नया प्रेस एक्ट पत्रकारों और पत्रकारिता के लिए मददगार होगा। यह कार्यक्षमता में वृद्धि करेगा, पत्रकारिता को संरक्षण प्रदान करेगा और इसकी विश्वसनीयता को बढ़ाएगा। वरिष्ठ पत्रकारों ने पत्रकारों से आग्रह किया कि वे समयबद्धता का पालन करें, निर्भय और निडर होकर पत्रकारिता करें, और पत्रकारिता की गरिमा और आचरण का पालन करें। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के पत्रकारों को समाज में सम्मान पाने के लिए बेहतर आचरण रखना चाहिए। कार्यशाला में कहा गया कि तकनीकी युग में न्यूज़ का स्वरूप बदल रहा है और पत्रकारिता का दायरा बढ़ रहा है। पत्रकारों को तकनीकी बदलावों के साथ तालमेल बिठाते हुए अपनी मूल पत्रकारिता और विश्वसनीयता को बनाए रखना होगा। वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि पत्रकारिता मिशन है, व्यवसाय नहीं। इसे दिल से और दिमाग से करना चाहिए। पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों को जीवित रखना होगा और पत्रकारिता के आचरण के मानकों का पालन करना होगा। यह कार्यशाला संभागीय जनसंपर्क कार्यालय इंदौर द्वारा 'प्रेस एक्ट और पत्रकारिता के आचरण के मानक' विषय पर आयोजित की गई थी। कार्यशाला में वरिष्ठ पत्रकार श्री रघुवीर तिवारी भोपाल, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री अरविंद तिवारी, स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री प्रवीण खारीवाल और वरिष्ठ पत्रकार श्री नवनीत शुक्ला ने मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन श्री संजय लाहोटी ने किया। कार्यशाला में बड़ी संख्या में पत्रकारगण मौजूद थे।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।